प्रदेश सोन के 1.25 मिलियन एकड़ फुट जल का उपयोग कर सकता है।

(ख) और (ग) अन्तरराज्यीय एवं अन्य मामलों का निपटान न होने के कारण केन्द्र सरकार ने इस परियोजना का अनुमोदन नहीं किया है। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च, 1998 तक इस परियोजना पर 40.92 करोड़ रुपए का व्यय कर दिया है।

उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के मध्य सोन नदी के जल का बंटवारा

1855. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार ने वर्ष 1973 में सोन नदी के जल के बारे में एक समझौता किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयोग ने नदी के कुल जल का आकलन 16.37 एस०ए०एफ किया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि जल के बंटवारे पर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के मध्य क्रमशः 1.25, 7.5 और 5.25 एस०ए०एफ० की मात्रा पर सहमति हुई थीं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1993 में प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद भी केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अन्तिम निर्णय न करने से यह समझौता लागू नहीं किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा गठित किए गए सोन नदी आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें इन्द्रापुरी में सोन बेसिन की पैदावार 75% विश्वसनीयता पर 16.37 मिलियन एकड़ फुट दिखाई गई थी।

(ग) समझौते के अनुसार उत्तरप्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लिए जल का आबंटन क्रमशः 1.25, 7.75 और 5.25 मिलियन एकड़ फुट है।

(घ) जी, नहीं। तथापि सभी बेसिन राज्यों के सहमत न होने के कारण सोन नदी आयोग द्वारा आकलित अतिरिक्त जल का आबंटन नहीं किया गया है।

Recommendations by Dr. Alagh Committee on Cauvery Water Dispute

1856. SHRI S. M. KRISHNA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether his Ministry have gone into the recommendations given by Dr. Alagh Committee set up regarding Cauvery water dispute; if so the details of such study including the reaction thereto;

(b) whether Government have agreed to implement the recommendations of the said Committee; and

(c) what are the salient points of Dr. Alagh Committee report and specific amongst them from practical point of view?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) to (c) Ministry of Water Resources appointed an Expert Group on 2nd January, 1996 comprising of Dr. Y.K. Alagh, Dr. Bharat Singh and Mr. S.P. Caprihan for an On-the-Spot Assessment of the standing crops in the Mettur Ayacut area of Tamil Nadu and Cauvery Ayacut area in Karnataka in connection with suit filed by Tamil Nadu in December, 1995 in the Supreme Court. The Expert Group submitted its report on 19th January, 1996 to Ministry of Water Resources. The main recommendations *inter-alia* contained in the report are as below:—

(i) Keeping in view, the shortage of water in both States, Karanataka must ensure availability of 11.4 TMC of water as due to Tamil Nadu from January to May.

(ii) However, to mitigate the problem of shortage in Tamil Nadu particularly in the months of January February and March when the demand will be at peak, the availability during these months may be augmented so as to enhance availability at Mettur Dam of an additional